>

Title: Need to take measures for the welfare of farmers in the country.

श्री नीरज शेखर (बलिया): मैडम, पिछले 10-12 सालों में देश में दो लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्यांए की हैं। देश की 65 से 70 प्रतिशत आबादी आज भी खेती से अपनी रोजी-रोटी चला रही है, पर आज किसान सबसे बदहाल स्थिति में है। पूरी दुनिया में उपलब्ध जमीन का केवल 10 प्रतिशत ही खेती के उपयुक्त है जबकि हमारे देश में 57 प्रतिशत जमीन खेती के लिए उपलब्ध है। इतनी अच्छी स्थिति में जमीन उपलब्धता के बावजूद भी इस देश में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं।

पिछले बीस सालों में सरकार द्वारा खाद, बीज, बिजली और डीजल के दामों में कई गुना वृद्धि की गयी, पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में उस रफ्तार से वृद्धि नहीं की। कभी 10 पैसे तो कभी 20 पैसे और चुनावी मौसम में 1 रुपए तक की वृद्धि की गयी। परिणामस्वरूप कभी सबसे सम्मानित पेशा कृषि किसानों की उत्तरोत्तर गरीबी और कर्ज का कारण बन गया।

आज देश में 80 प्रतिशत किसानों के पास 2 हैक्टेयर से कम की जोत है और वो 4 लोगों के परिवार का खर्च इस खेती से वहन करने में पूरी तरह अक्षम है। कारण कृषि का अलाभकारी और खर्चीला होना।

अतः सरकार किसानों के हित के लिए एवं कृषि को लाभकारी बनाने के लिए गेंहू और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 से 25 रुपए प्रति किलो करें और गरीबों (बी.पी.एल.) हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित कर 2 से 3 रुपए प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराएं एवं किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। उनको 3 प्रतिशत की दर से ऋण की व्यवस्था करें और कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए तत्काल एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करें।